जीडीपी में विनिर्माण क्षेत्र का शेयर 45% तक बढ़ाने का रोडमैप तैयार

डब्ल्यूईएफ व राज्य सरकार की संयुक्त कार्यशाला में मुख्य सचिव ने पेश की रूपरेखा

अमर उजाला ब्यूरो

राज्य सरकार और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के सहयोग से पिकप भवन में शनिवार को हुई कार्यशाला को संबोधित करते मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह। -विभाग

लखनऊ। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने कहा कि राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में विनिर्माण क्षेत्र का योगदान 25 से बढ़ाकर 45 प्रतिशत करना है। इसके लिए उद्योग यूपी में आकर यहां की नीतियों का लाभ उठा सकते हैं। कहा, यह पहल प्रदेश को 10 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था में बदलने के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दृष्टिकोण के साथ मेल खाती है। वे शनिवार को राज्य सरकार और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (डब्ल्यूईएफ) के सहयोग से पिकप भवन में हुई कार्यशाला में बोल रहे थे।

उन्होंने प्रदेश को उन्नत विनिर्माण के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र और वैश्विक आर्थिक गतिविधियों के केंद्र के रूप में स्थापित करने की विस्तार से जानकारी दी। इस कार्यशाला का उद्देश्य यूपी में देश के पहले उन्नत विनिर्माण केंद्र की स्थापना की नींव रखना था। यह केंद्र अत्याधुनिक तकनीकों, डिजिटलीकरण और नवाचार के लिए हब के रूप में स्थापित होगा। इसका उद्देश्य देश को वैश्विक उन्नत विनिर्माण के क्षेत्र में अग्रणी बनाना है। डब्ल्यूईएफ फोरम के सेंटर फॉर द फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन नेटवर्क की एशिया प्रमुख वंदना मेनन ने वैश्विक केंद्र की योजना पेश की। कार्यशाला में पीटीसी इंडस्ट्रीज, मारुति सुजुकी, आदित्य बिड़ला ग्रुप, हायर, जेके सीमेंट, अशोक लीलैंड, ग्रीनलैम, हुंडई इंडिया, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, आरएसीएल ग्रीनटेक लिमिटेड, भारतीयम बेवरेजेज सहित 40 से अधिक प्रमुख कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल हुए।